दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स बिहार

फरवरी (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

बिहार **3**

- श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता 3
- पुनौरा धाम 3
- इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ महावीर कैंसर संस्थान का करार 4
- विश्वस्तरीय जीनोमिक लैब 4
- कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल 4
- रेल कौशल विकास योजना 5
- फोर्टीफाइड चावल वितरण को मंज़ूरी 5
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 6
- मुंगेर में गंगा नदी पर निर्मित रेल-सह-सड़क पुल की पहुँच पथ परियोजना का लोकार्पण 6
- सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊँची प्रतिमा 7
- बिहार विधानसभा का डिजिटलीकरण 7
- तारापुर शहीद स्मारक 8
- राजगीर ज़ू सफारी 8
- बिहार विधानमंडल में प्रबोधन कार्यक्रम 8
- सकीबुल गनी 9
- युवा संसद प्रतियोगिता 9
- सीएम के भाषण के संकलन की किताब का विमोचन 10
- बिहार में भी BSNL की 4जी सेवा होगी लॉन्च 10
- बिहार की पहचान मैथिली बत्तख 11
- वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व 11
- अंतरिक्ष में होने का अहसास कराएगा पटना का अत्याधुनिक तारामंडल 11
- नेशनल मिशन फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम 12
- स्वाइन फीवर 12
- बिहार डिजिपेक्स, 2022 13
- राज्य के 100 एपीएचसी बनेंगे मॉडल अस्पताल 13
- बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 14
- बिहार पुलिस सुधार 15

नोट :

दृष्टि The Vision

बिहार

श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता

चर्चा में क्यों ?

- 31 जनवरी, 2022 को बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर के 149 सरकारी ITI को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने और छात्रों को बेहतर रोज़गार से जोड़ने के लिये टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि इस समझौते के बाद सरकारी ITI में पढ़ाई करने वाले छात्र देश-दुनिया में आज की तकनीक के आधार पर रोज़गार ले पाएंगे और देश को बेहतर मानव संसाधन मिल पाएगा।
- बिहार, इस तरह का समझौता करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले इस तरह का कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया था।
- इस समझौते के बाद राज्य का प्रौद्योगिकी परिदृश्य बदल जाएगा। राज्य के युवाओं के लिये बेहतर कौशल और रोज़गार के अवसर उपलब्ध होगा। यह राज्य में उन उद्योग प्रतिष्ठानों के लिये संभावित निवेश के रूप में भी स्थापित होगा, जो उद्योग 4.0 और विनिर्माण के लिये स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने को इच्छुक हैं।
- अब ITI में 23 नई तकनीक के उन्नत व्यापार पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेंगे। इस परियोजना के तहत कुल निवेश 4,606 करोड़ रुपए होगा।
- इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव वंदना किनी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में बिहार के युवाओं को प्रशिक्षित और सशक्त बनाना, ताकि वे बिहार में नए प्रौद्योगिकी समाधानों को खोज सकें और साथ ही कंपनियों से निवेश आकर्षित कर रोज़गार सृजित कर सकें।
- उन्होंने कहा कि पहले चरण में दिसंबर 2022 तक 60 केंद्र अपग्रेड होंगे। वहीं, बाकी 89 केंद्रों को विकसित करने का काम जनवरी 2023 में प्रारंभ किया जाएगा, जो 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा होगा। इस काम में सहयोगी के रूप में 16 कंपनियाँ हैं, जो ITI को विकसित करने के लिये काम करेंगी।

पुनौरा धाम

चर्चा में क्यों ?

- 3 फरवरी, 2022 को पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी द्वारा राज्यसभा में बताया गया कि बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में तथा प्रसाद योजना में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के पुनौरा धाम गाँव में माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जिसे ही पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है।
- गौरतलब है कि प्रसाद योजना सभी धर्मों के तीर्थ केंद्रों पर सुविधाओं और अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी।
- वहीं स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिये वर्ष 2014-15 में प्रारंभ की गई थी, जैसे- रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट आदि।
- बिहार में प्रसाद योजना के अंतर्गत पटना साहिब का विकास तथा स्वदेश दर्शन योजना के तहत जैन परिपथ का विकास, कांवरिया परिपथ का विकास, गांधी परिपथ का विकास, रामायण सर्किट एवं बौद्ध परिपथ शामिल हैं।

नोट :

इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ महावीर कैंसर संस्थान का करार

चर्चा में क्यों?

- 4 फरवरी, 2022 को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पटना जंक्शन के समीप स्थित पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल 'महावीर कैंसर संस्थान' में कैंसर की शुरुआती जाँच नि:शुल्क करने के लिये इस संस्थान ने इंडियन कैंसर सोसाईटी के साथ करार किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने नि:शुल्क कैंसर परामर्श शिविर का उद्घाटन किया।
- आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि कैंसर के लक्षण दिखने पर महावीर करार संस्थान में 25 हज़ार रुपए तक की जाँच भारतीय कैंसर समिति के सहयोग से नि:शुल्क होगी।
- चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एलवी सिंह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिये महावीर कैंसर संस्थान को अवार्ड भी दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि महावीर कैंसर संस्थान में पड़ोसी राज्यों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश तक के मरीज कैंसर के इलाज के लिये आते हैं। यह संस्थान गरीब कैंसर मरीजों के लिये आस्था का केंद्र बन गया है। 1998 में दलाई लामा ने इस संस्थान का शुभारंभ किया था, इसमें प्रतिदिन औसतन लगभग 300 मरीजों की कीमोथेरेपी और इतने ही मरीजों की रेडियोथेरेपी की जाती है।

विश्वस्तरीय जीनोमिक लैब

चर्चा में क्यों?

- 4 फरवरी, 2022 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर में कैंसर जाँच के लिये स्थापित विश्व स्तरीय जीनोमिक लैबोरेटरी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस साल से राज्य के सभी जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले साल राज्य के 16 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- स्वास्थ्य विभाग की ओर से छह मेडिकल कॉलेजों में डे-केयर कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही छह जिलों में कैंसर के मरीजों को होने वाले दर्द का इलाज घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि बिहार में कैंसर मरीजों का 2020 तक सालाना बोझ दो लाख होता था, जो 2025 तक बढ़ कर 2 लाख 32 हज़ार सालाना हो जाएगा।
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में महावीर कैंसर संस्थान को विकसित करने की दिशा में सभी सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य के छह जिलों- पटना, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, सिवान और नालंदा में कैंसर के मरीजों के दर्द का इलाज घर पर किया जाएगा। इसके अलावा डे केयर कीमोथेरेपी की व्यवस्था एनएमसीएच, वीम्स, पावापुरी, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, डीएमसीएच और पूर्णिया सदर अस्पताल में की गई है।

कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल

चर्चा में क्यों?

- 5 फरवरी, 2022 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने पटना से गुवाहाटी के लिये अंतर्देशीय जलमार्ग पोत एमवी लाल बहादुर शास्त्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का निर्माण बिहार के सारण ज़िले में गंगा नदी पर 78.28 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। एक बर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता 77,000 टीईयू प्रति वर्ष होगी और टर्मिनल को कंटेनर ट्रैफिक को संभालने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इस टर्मिनल के निर्माण से उत्तर बिहार में सड़क परिवहन पर दबाव कम होने के साथ ही इस क्षेत्र में विशेष रूप से नेपाल के लिये कार्गो के परिवहन के लिये एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।
- अंतर्देशीय जलमार्ग पोत एमवी लाल बहादुर शास्त्री पटना के गायघाट बंदरगाह से गुवाहाटी स्थित पांडु के लिये 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न ले जा रहा है। यह बांग्लादेश से होते हुए मार्च 2022 की शुरुआत तक गंतव्य स्थल तक पहुँचेगा।
- यह पोत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) के भागलपुर, मनिहारी, साहिबगंज, फरक्का, ट्रिबेनी, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर से होते हुए यात्रा करेगा। इससे आगे यह इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) के खुलना, नारायणगंज, सिराजगंज, चिलमारी और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-2 के धुबरी व जोगीघोपा होते हुए 2,350 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
- पटना (बिहार) से पांडु (गुवाहाटी) तक जहाज़ पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही से 'गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट'(असम) के लिये एक नया द्वार खुलेगा और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये निर्बाध जलमार्ग कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
- इस ऐतिहासिक उपलब्धि से उत्तर-पूर्व भारत के सभी राज्यों के लिये विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह जलमार्ग उन भूबंधित क्षेत्रों से होकर जाएगा, जो लंबे समय से विकास के संबंध में पिछड़ा हुआ है। यह जलमार्ग न केवल इस क्षेत्र में प्रगति की राह में भौगोलिक बाधा को दूर करता है, बल्कि व्यापार व इस क्षेत्र के लोगों के लिये एक सस्ता, तेज और सुविधाजनक परिवहन भी प्रदान करता है।

रेल कौशल विकास योजना

चर्चा में क्यों?

- 7 फरवरी, 2022 को 'रेल कौशल विकास योजना'(आरकेवीवाई) के तहत प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के बाद सिग्नल एवं दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, दानापुर (बिहार) में 16 योग्य प्रशिक्षुओं को पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सिग्नल इंजीनियर द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, बिजली आपूर्ति, सोल्डरिंग, मल्टीमीटर, ट्रांसफार्मर के उपयोग और मरम्मत आदि का प्रशिक्षण दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि युवाओं में कौशल विकास के लिये भारत सरकार के रेल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 17 सितंबर, 2021 को 'रेल कौशल विकास योजना'शुरू की गई थी।
- 'रेल कौशल विकास योजना'स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'के तहत भारतीय रेलवे द्वारा अपनाए गए कौशल भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है।
- 'रेल कौशल विकास योजना'के तहत 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कार्य दिवसों में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- इस योजना से युवाओं की रोज़गार क्षमता में सुधार होगा और स्वरोज़गार करने वाले युवाओं के कौशल में उन्नयन होगा।

फोर्टीफाइड चावल वितरण को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

- 8 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी राशन की दुकान से फोर्टीफाइड चावल वितरण की केंद्र सरकार की योजना को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके की 85 फीसदी और शहरी इलाके की 75 फीसदी आबादी को पोषणयुक्त चावल (Nutritious Rice) मिलेगा, जो आयरन, फ्लोरिक एसिड और विटामिन बी-12 से युक्त होगा।

- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और मिड-डे-मील योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित चावल के फोर्टिफिकेशन की घोषणा की है।
- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिये चावल का फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है।
- FSSAI के अनुसार, फूड फोर्टीफिकेशन का संबंध भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने से है, ताकि भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार हो और स्वास्थ्य के लिये न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना

चर्चा में क्यों?

- 10 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में 'मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना -2' के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' की प्रगति की समीक्षा की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन 15 अप्रैल से शुरू करने के निर्देश दिये गए।
- प्रायोगिक तौर पर इसे सभी ज़िलों के कम-से-कम एक-एक पंचायत में शुरू कराया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य में गाँवों के रास्ते और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सोलर लाइट लगाई जाएगी।
- इसके लिये पूर्व में ही प्रत्येक गाँव के मुखिया को सर्वे करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी। सर्वे में गाँव और उस जगह का चयन करने को कहा गया था, जहाँ सोलर लाइटें लगाई जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं-
  - बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
  - हर घर बिजली योजना
  - घर तक पक्की नाली-गलियाँ
  - अवसर बढ़ें, आगे बढ़ें
  - हर घर नल का जल योजना
  - आरक्षित रोज़गार महिलाओं का अधिकार योजना
  - शौचालय निर्माण, घर का सम्मान

मुंगेर में गंगा नदी पर निर्मित रेल-सह-सड़क पुल की पहुँच पथ परियोजना का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 11 फरवरी, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के मुंगेर में गंगा नदी पर 'रेल-सह-सड़क पुल' की पहुँच पथ परियोजना का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुंगेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 333बी पर गंगा नदी के ऊपर निर्मित रेल-सह-सड़क पुल के लिये 14.5 किमी लंबी पहुँच सड़क को कुल 696 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है।
- यह 'रेल-सह-सड़क पुल' बिहार में गंगा नदी पर निर्मित तीसरा रेल-सह-सड़क पुल है, जो मुंगेर-जमालपुर शहरों को बेगूसराय, खगड़िया और उत्तर बिहार के विभिन्न ज़िलों से जोड़ेगा।

- 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी ने रेल-सह-सड़क पुल की नींव रखी थी। बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार उस समय वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे।
- इस पुल की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी, जिसे निम्न प्रकार देखा जा सकता है-
  - 1953 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी मुंगेर के लोगों से वादा किया था कि नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा।
  - 1971 में इंदिरा गांधी ने एक चुनाव प्रचार के दौरान इसी तरह के आश्वासन दोहराए थे।
  - रेल-सह-सड़क पुल को अंततः 1997-98 के रेल बजट में (पूरक अनुदान के माध्यम से) सांकेतिक आवंटन प्राप्त हुआ।

सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊँची प्रतिमा

चर्चा में क्यों?

- 13 फरवरी, 2022 को रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल को-ऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी विरेंद्रानंद जी महाराज ने माता सीता की विश्व की सबसे ऊँची (251 मीटर) प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- काउंसिल ने इसके कार्यान्वयन के लिये श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया है जिसका अध्यक्ष स्थानीय सुनील सांसद सुनील कुमार पिंटू को बनाया गया है।
- माता सीता की 251 मीटर ऊँची प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में भगवती सीता की 108 प्रतिमाएँ भी स्थापित की जाएंगी जो उनके जीवन-दर्शन को अभिव्यक्त करेंगी। इन प्रतिमाओं के दर्शन के लिये इस स्थल को नौका विहार की तरह विकसित किया जाएगा।
- यहाँ पर भगवती सीता के जीवन दर्शन पर आधारित एक डिजिटल म्यूजियम, शोध संस्थान और अध्ययन केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा।
- यहाँ पर तुलसीदास, वाल्मिकी, केवट समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की प्रतिमाएँ भी स्थापित होंगी।
- इस अवसर पर माता सीता डॉट कॉम वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है जिस पर मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य की जानकारी को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
- सीता कुंड बिहार राज्य में सीतामढ़ी नगर के समीप पुनौरा ग्राम स्थित सीता कुंड एक हिन्दू तीर्थ स्थल है। पुनौरा धाम जानकी कुंड (Punaura Dham Janki Kund) पौराणिक काल में पुंडरिक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था।

बिहार विधानसभा का डिजिटलीकरण

चर्चा में क्यों?

- 14 फरवरी, 2022 को विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के डिजिटलीकरण के संदर्भ में बताया कि विधायकों के निजी सचिवों को इस संदर्भ में विधानसभा की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- विधानसभा में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से सभी अधिकारी व कर्मियों को डिजिटली साक्षर बनाया जाएगा।
- विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा।
- गौरतलब है कि विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में 17 फरवरी को प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया। इस कार्यक्रम का विषय 'लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण व उत्तरदायित्व' था।

नोट :

तारापुर शहीद स्मारक

चर्चा में क्यों ?

- 15 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक तारापुर, मुंगेर में शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया तथा शहीद पार्क एवं पुराना थाना परिसर में पार्क विकास कार्य का भी लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के तारापुर में एक साथ 34 लोग शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में अब प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद स्मारक पर राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को शहीदों की जानकारी हो सके और लोगों को इन पर गौरव महसूस हो।
- कॉन्ग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शार्दुल सिंह कविष्कर ने 15 फरवरी, 1932 को सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। 13 फरवरी, 1932 को सुपौर के जमुआ गाँव में निर्णय लिया गया और मदन गोपाल सिंह के नेतृत्व में 5 स्वयंसेवकों का धावा दल गठित किया गया।
- 14 फरवरी को लोग धावा दल के साथ तारापुर पहुँचे और 15 फरवरी, 1932 को इन लोगों ने धावा बोल दिया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के कारण सब लोग भागने लगे, लेकिन मदन गोपाल सिंह ने अपनी जेब में रखे झंडे को थाने पर फहरा दिया और वहाँ लोग 'झंडा ऊँचा रहे हमारा' नारा लगाने लगे।
- उत्साहित लोगों द्वारा पुलिस पर किये गए पथराव से घायल ज़िलाधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 34 लोग शहीद हो गए, किंतु इनमें 13 लोगों के ही नाम का पता चल पाया। तारापुर की यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के लिये महत्त्वपूर्ण है।

राजगीर ज़ू सफारी

चर्चा में क्यों ?

- 16 फरवरी, 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में ज़ू सफारी का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 480 एकड़ में फैले ज़ू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया है जिसका शिलान्यास वर्ष 2016 में किया गया था।
- सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री थ्री डी थिएटर का भी निर्माण किया गया है। व्याख्या केंद्र में मानव के विकास क्रम और वन्यजीवों के जीवन चक्र से जुड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष 'द ओसियन बॉयोस्कोप' फिल्म प्रदर्शित की गयी।
- इस ज़ू सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरण रखने का निर्णय किया गया है जिनके लिये पाँच अलग-अलग बड़े एन्क्लोजार (बाड़े) बनाए गए है।
- उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ग्लास स्काई वाक का भी निर्माण किया गया है।

बिहार विधानमंडल में प्रबोधन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

- 17 फरवरी, 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन स्थित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल सदस्यों के लिये आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रबोधन कार्यक्रम का विषय था- 'लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों का उन्मुखीकरण एवं उत्तरदायित्व'।

नोट :

- बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष एवं स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लोकसभा तथा बिहार विधानसभा, सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
- गौरतलब है कि वर्ष 2006 में पहला प्रबोधन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी मारगेट अल्वा शामिल हुई थीं। उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी थे।
- वर्ष 2011 के दूसरे प्रबोधन कार्यक्रम में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली शामिल हुए थे। तीसरे प्रबोधन कार्यक्रम में संसदीय मामले के विशेषज्ञ जे.सी. मल्होत्रा शामिल हुए थे।
- विदित है कि 22 मार्च, 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए तथा 1920 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 7 फरवरी, 1921 को विधानमंडल की पहली बैठक हुई थी। विधानमंडल भवन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हाल ही में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- अक्तूबर 2021, में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद शामिल हुए थे। उन्होंने बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया था और बोधगया से लाए गए पवित्र बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया था।

सकीबुल गनी

चर्चा में क्यों?

- 18 फरवरी, 2022 को कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय के मैदान में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मैच में पूर्वी चंपारण के सकीबुल गनी ने अपने डेब्यू मैच में ही तिहरा शतक लगाते हुए इतिहास रच दिया।

प्रमुख बिंदु

- सकीबुल गनी ने बिहार टीम की ओर से मिज़ोरम के खिलाफ खेलते हुए 405 गेंद में 341 रन (56×4 व 2×6) की शानदार पारी खेली।
- इनकी शानदार पारी की बदौलत बिहार ने प्रथम पाली में 148.5 ओवर में 609 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब किसी बल्लेबाज़ ने तिहरा शतक लगाया हो। साथ ही, रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सबसे बड़ा स्कोर का राष्ट्रीय कीर्तिमान भी सकीबुल गनी ने अपने नाम कर लिया।
- इसके पहले यह कीर्तिमान मध्य प्रदेश के बल्लेबाज़ अजय रोहेड़ा के नाम था। अजय ने 2018 में अपने डेब्यू मैच में हैदराबाद के खिलाफ नाबाद 267 रन बनाए थे।
- 22 वर्षीय सकीबुल गनी मोतिहारी शहर के मोहल्ला अगरवा के निवासी हैं। इनके पिता मो.मन्नान गनी हैं। इन्होंने विगत दो-तीन सत्र से BCCI द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्द्धाओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इन्होंने वर्ष 2015 में अंडर-14, 2016-17 में अंडर-19 तथा 2017 व 18 में बिहार अंडर-23 के अलावा 2019 व 2021 के विजय हज़ारे सीनियर ट्रॉफी, 2020 में चेन्नई और 2021 में दिल्ली में आयोजित मुश्ताक अली (20-20) व विजय हज़ारे (50-50) ट्रॉफी में भी बेहतर प्रदर्शन किया था।

युवा संसद प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों?

- 18 फरवरी, 2022 को बिहार में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में ज़िला स्तर पर नालंदा के आठ छात्रों का चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ये चयनित छात्र राज्यस्तर पर 23 से 27 फरवरी, 2022 तक होने वाली प्रतियोगिता में ज़िले का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- इनमें से चयनित छात्रों को 8 व 9 मार्च, 2022 तक को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
- यह प्रतियोगिता पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एनएसएस द्वारा ऑनलाइन कराई गई थी। इनमें से चार छात्र एवं चार छात्राओं का चयन किया गया है।

नोट :

- नालंदा कॉलेज एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रतियोगिता के जज डॉ. बिनीत लाल ने बताया कि चयनित विद्यार्थियों ने युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित छह विषयों में से एक विषय पर अपने विचार रखे थे।
- नालंदा कॉलेज से मानसी कुमारी, अमित कुमार, अमर राज तथा नालंदा महिला कॉलेज से अर्पिता राज, शोभा कुमारी और किसान कॉलेज से सपना कुमारी, सन्नी प्रशांत, सन्नी कुमार का इस प्रतियोगिता में चयन हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि 12 जनवरी, 2018 को 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़िला युवा संसद को आयोजित करने का विचार व्यक्त किया। इसके पश्चात् जनवरी-फरवरी 2019 में पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया।
- युवा संसद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य 2022 के न्यू इंडिया विजन के लिये 18 से 25 वर्षीय युवाओं के विचार जानना और उन्हें इसमें शामिल करना।

सीएम के भाषण के संकलन की किताब का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 18 फरवरी, 2022 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानपरिषद में दिये गए भाषण के प्रकाशित संग्रह पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- उपसभापति ने कहा कि 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के बीमारू राज्य वाली छवि को बदल दिया तथा अपने काम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है।
- विमोचित किताब का नाम 'माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानपरिषद में दिये गए भाषण के प्रकाशित संग्रह' है।
- इस पुस्तक में विधानपरिषद के 151वें से 195वें सत्र के दौरान दिये गए मुख्यमंत्री के भाषण संकलित किये गए हैं।
- कार्यक्रम का आयोजन विधानपरिषद के उपभवन स्थित सभागार में किया गया।

बिहार में भी BSNL की 4जी सेवा होगी लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

- 19 फरवरी, 2022 को BSNL बोर्ड के निदेशक सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार में आगामी 15 अगस्त को 4जी सेवा लॉन्च की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये बिहार में BSNL 4जी के 4 हज़ार टावर लगाए जाएंगे।
- ज्ञातव्य है कि BSNL को 4जी का स्पेक्ट्रम मिल चुका है। बिहार में अभी 2जी और 3जी के 2 हज़ार 800 मोबाइल टावर हैं। सभी को 4जी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। बिहार के साथ दिल्ली और मुंबई में भी BSNL की 4जी समीक्षा सेवा शुरू होगी।
- BSNL पूरी तरह में 2जी स्वदेशी उपक्रमों के साथ 4जी सेवा मोबाइल लॉन्च करेगी। टीसीएस स्वदेशी 4जी का उपक्रम बना रहा है। साथ ही 4जी की लॉन्चिंग के साथ 5जी का भी ट्रायल शुरू हो जाएगा।
- BSNL के मुख्य महाप्रबंधक देवेंद्र ने बताया कि अन्य टेलीकॉम कंपनियाँ अपना टैरिफ बढ़ा रही हैं, लेकिन BSNL रियायती दरों पर मोबाइल सेवाएँ दे रही है। पिछले महीने में BSNL बिहार ली परिमंडल में दो लाख उपभोक्ता जुड़े हैं।

बिहार की पहचान मैथिली बत्तख

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में उत्तर बिहार में पाए जाने वाली मैथिली बत्तख का नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल में नाम दर्ज़ कर लिया गया है। मैथिली बत्तख अब बिहार की पहचान बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के वैज्ञानिकों की टीम ने छह साल तक बत्तख पर रिसर्च करने के बाद नामकरण किया है।
- ये बत्तख देशभर में पसंद किए जा रही हैं। मैथिली बत्तख पर काम करने वाली डॉ. रीना कमल ने बताया कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और मोतिहारी क्षेत्र में बत्तख का देसी नामकरण किया गया है।
- यह अपने इस आकर्षक रंग, हल्के वज़न और यहाँ के वातावरण में ज़िंदा रहती हैं। इनके इलाज में कम खर्च होता है। यही नहीं कम ज़मीन पर इन्हें पाला जा सकता है। इनका मीट औषधीय गुणों से भरपूर है। राज्य में 50-60 हज़ार मैथिली बत्तख हैं। मत्स्यपालन में भी मैथिली बत्तख साथी बन रहे हैं। इन्हें दूसरी विदेशी नस्ल की बत्तखों से पाल खाने से बचाया जा रहा है। ये बत्तख कम अंडे देती हैं, इसलिये किसान दूसरी बत्तखों से पाल खिला देते हैं। इससे मैथिली बत्तखों के अस्तित्व पर खतरा मँडरा रहा है। ICAR किसानों को जागरूक कर इनको विलुप्त होने से बचाने की कोशिश में लगा है।
- संस्थान में मैथिली बत्तख की पहचान के साथ इसके विकास और अंडे की क्षमता को बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है।

वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

- 19 फरवरी, 2022 को वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के वन प्रमंडल दो के मदनपुर वन क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर आग लगा दी गई, जिससे VTR प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष शाकाहारी जानवरों को खाने के लिये आरोपित की जाने वाली घास और वृक्षों को काफी नुकसान पहुँचा है।

प्रमुख बिंदु

- वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिज़र्व है, जो भारत में हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है।
- गंगा के मैदान जैव-भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस टाइगर रिज़र्व की वनस्पति भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है।
- बाघ गणना, 2018 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या 32 है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2021 के अनुसार इसके कुल क्षेत्रफल के 85.71% भू-भाग पर वनावरण विद्यमान है।
- वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में बाघ, सुस्त भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सूअर आदि शामिल हैं।

अंतरिक्ष में होने का अहसास कराएगा पटना का अत्याधुनिक तारामंडल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में कोलकाता से आई 6 सदस्यीय टीम ने पटना स्थित तारामंडल का निरीक्षण किया, जिसके उपरांत इस तारामंडल को डिजिटल बनाने का कार्य शुरू हो गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पटना तारामंडल देश का पहला ऐसा तारामंडल होगा, जहाँ 6 रेड, ग्रीन और ब्ल्यू (आरजीबी) प्योर लेज़र प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे। इन प्रोजेक्टर में रंगों के अनेक प्रकार हैं।
- ये प्रोजेक्टर आरजीबी किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिलाकर शो के लिये वास्तविक रंगों का निर्माण करेंगे, जिससे दर्शकों को तारामंडल में अंतरिक्ष में होने का अहसास होगा।
- यह प्रोजेक्शन सिस्टम 16 मीटर डायमीटर डोम एरिया के अनुरूप उपयुक्त एवं आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसकी कुल लागत 36 करोड़ 13 लाख 20 हज़ार रुपए होगी।
- इस प्रोजेक्टर से 2डी और 3डी शो देखने की सुविधा मिलेगी।
- गौरतलब है कि देश में 22 तारामंडल हैं, जिनमें से कोलकाता साइंस सिटी और कर्नाटक पिलिकुला स्वामी विवेकानंद प्लेटरियम में 3डी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। बाकी सभी तारामंडलों में 2डी प्रोजेक्टर लगे हैं।
- विदत है कि बिहार में पटना के अलावा गया और भागलपुर में भी तारामंडल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- आरजीबी प्योर लेज़र प्रोजेक्टर की आयु 40 हज़ार से अधिक घंटे की होती है। इसमें कूलिंग सिस्टम लगा रहता है। इस प्रोजेक्टर से आँखों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। डिजिटल प्रोजेक्टर की अपेक्षा इसमें ब्राइटनेस अधिक होती है।

नेशनल मिशन फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम

चर्चा में क्यों?

- 21 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में भारत सरकार की बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणाली योजना (NM-ICPS) के तहत प्रौद्योगिकी विकास, कौशल विकास, उद्यमिता एवं स्टार्टअप विषयों में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र के रूप में आईआईटी रूड़की के 'दिव्या संपर्क इनोवेशन हब' को मनोनीत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- NM-ICPS एक समग्र मिशन है, जो साइबर फिजिकल सिस्टम में प्रौद्योगिकी विकास, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता और स्टार्टअप विकास तथा संबंधित प्रौद्योगिकियों के मुद्दों को हल करेगा।
- मिशन का लक्ष्य 15 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, 6 विनियोग नवाचार केंद्र और 4 प्रौद्योगिकी आधारित नव अनुसंधान केंद्र बनाना है।
- इस मिशन को वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिये मंज़ूरी प्रदान की गई थी।

स्वाइन फीवर

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बिहार के सारण ज़िले में एक हज़ार से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है, जिसके लिये प्रथमदृष्टया स्वाइन फीवर को उत्तरदायी माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि स्वाइन फीवर एक संक्रामक पशु रोग है। इसके मुख्यत: दो प्रकार होते हैं-

1. अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF)

- यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक पशु रोग है, जो घरेलू और जंगली सूअरों को संक्रमित करता है तथा रक्तस्रावी बुखार का एक तीव्र रूप धारण कर लेता है।
- ASF मनुष्यों के लिये खतरा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है।

2. क्लासिकल स्वाइन फीवर (CSF)

- सीएसएफ को हॉग हैज़ा के नाम से भी जाना जाता है।
- यह फ्लेविविरिडे परिवार के जीनस पेस्टीवायरस के वायरस के कारण होता है, जो उन वायरस से निकटता से संबंधित है, जो मवेशियों में गोजातीय वायरल दस्त और भेड़ में बॉर्डर रोग का कारण बनते हैं।
- ICAR-IVRI ने विदेशी स्ट्रेन से लैपिनाइज्ड वैक्सीन वायरस का उपयोग कर एक सेल कल्चर सीएसएफ वैक्सीन (लाइव एटेंयूएटेड) विकसित किया है।

बिहार डिजिपेक्स, 2022

चर्चा में क्यों?

- 24 फरवरी, 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पहली राज्यस्तरीय वर्चुअल डाक टिकट प्रदर्शनी 'बिहार डिजिपेक्स' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रदर्शनी का आयोजन 24 से 27 फरवरी तक बिहार डाक परिमंडल द्वारा किया जा रहा है जिसका विषय 'भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत' है।
- इस डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्देश्य डाक टिकट संग्रहण के शौक को बढ़ावा देने के साथ-साथ डाक टिकट संग्रहकर्ताओं, विशेषकर नवोदित और युवा डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और छात्रों को अपने संग्रह के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।
- उल्लेखनीय है कि डाक टिकट संग्रह (philately) को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग ने 'दीन दयाल स्पर्श योजना' की शुरुआत की थी।
- यह पूरे भारत के स्कूली बच्चों के लिये छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह को एक रुचि के रूप में चुना है।

राज्य के 100 एपीएचसी बनेंगे मॉडल अस्पताल

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में पहल करते हुए 100 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) को मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 एपीएचसी को मॉडल अस्पताल बनाए जाने से वहाँ गंभीर बीमारियों की जाँच व सभी बीमारियों के प्रारंभिक इलाज की सुविधा लोगों को प्राप्त होगी।
- इन 100 एपीएचसी में आधारभूत संरचना को मज़बूत करने, आवश्यकतानुसार कमरों के निर्माण, जाँच उपकरण इत्यादि के इंतजाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किये जाएंगे।
- राज्य स्वास्थ्य समिति ने केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष वर्ष 2022-23 के लिये प्रस्तावित योजना बजट प्रस्ताव के तहत एपीएचसी को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता जताई है। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दिये जाने व राशि आवंटित किये जाने के बाद क्रियान्वयन शुरू होगा।
- स्वास्थ्य उपकेंद्रों व एपीएचसी को उत्क्रमित कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं, मॉडल एपीएचसी में आधारभूत संरचना को मज़बूत कर वहाँ मरीज़ों को प्रारंभिक इलाज की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- एपीएचसी में एक चिकित्सक, दो एएनएम की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही गैर-संचारी रोगों, मधुमेह, रक्तचाप व अन्य बीमारियों की जाँच से जुड़ी सभी सुविधाएँ, टीकाकरण की सुविधा सहित टेलिमेडिसिन की सुविधाएँ भी इन अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएंगी।

नोट :

- इसके अलावा गर्भावस्था एवं शिशु जन्म देखभाल, नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएँ, संचारी रोग प्रबंधन, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं रेफरल व फॉलोअप की व्यवस्था के साथ अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी।

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

चर्चा में क्यों?

- 25 फरवरी, 2022 को बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन के पटल पर राज्य का 16वाँ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 2020-21 में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगाए गए 'लॉकडाउन' के प्रभाव के बावजूद वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
- सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा बाज़ार मूल्य पर 2020-21 के दौरान भारत के 86,659 रुपए प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपए रही।
- पिछले पाँच वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत की उच्चतम दर से वृद्धि हुई।
- राज्य में पिछले पाँच वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।
- 2020-21 में राज्य सरकार का कुल खर्च पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत बढ़कर 1,65,696 करोड़ रुपए पहुँच गया, जिसमें 26,203 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय और 1,39,493 करोड़ रुपए राजस्व व्यय शामिल है।
- पिछले पाँच वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। पशुधन और मत्स्य पालन की वृद्धि दर क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत रही।
- पिछले दस वर्ष में राज्य का शहरीकरण काफी तेज़ी से बढ़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर महज़ 11.3 प्रतिशत था, जो वर्तमान में 15.3 प्रतिशत हो गया है।
- वर्ष 2011 में देश की कुल शहरी आबादी का सिर्फ 3.1 प्रतिशत हिस्सा बिहार में था। राज्य सरकार ने उम्मीद जताई है कि उच्च दर से बढ़ रही शहरी अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगले दशक में बिहार में शहरीकरण का स्तर काफी ऊँचा होगा।
- सर्वेक्षण में बिहार के ज़िलों के बीच आर्थिक असमानता की तरह शहरीकरण में भी काफी असमानता बताई गई है। पटना ज़िले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक (44.3 प्रतिशत) है, इसके अतिरिक्त सिर्फ दो ज़िलों- मुंगेर (28.3 प्रतिशत) और नालंदा (26.2 प्रतिशत) में ही शहरीकरण का प्रतिशत 25 से अधिक है।
- वर्ष 2019-20 के आँकड़ों के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना ज़िला 131.1 हज़ार रुपए के साथ सबसे ऊपर है। वहीं दूसरे नंबर पर बेगूसराय ज़िला है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 51.4 हज़ार रुपए है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में इनके बाद मुंगेर (44.3 हज़ार), भागलपुर (41.8 हज़ार), रोहतास (35.8 हज़ार), मुज़फ्फरपुर (34.8 हज़ार), औरंगाबाद (32 हज़ार), गया (31.9 हज़ार), भोजपुर (31.6 हज़ार) और वैशाली (30.9 हज़ार रुपए) हैं।
- कम प्रति व्यक्ति आय वाले ज़िलों में शिवहर (19.6 हज़ार रुपए), अररिया (20.6 हज़ार), सीतामढ़ी (22.1 हज़ार), पूर्वी चंपारण (22.3 हज़ार), मधुबनी (22.6 हज़ार), सुपौल (22.9 हज़ार), किशनगंज (23.2 हज़ार) व नवादा (23.4 हज़ार रुपए) शामिल हैं।

नोट :

बिहार पुलिस सुधार

चर्चा में क्यों ?

- 27 फरवरी, 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस सप्ताह के समापन समारोह में कहा कि राज्य सकरार का लक्ष्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ाकर प्रति एक लाख आबादी पर 165 से 170 करना है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भारत में प्रति लाख व्यक्तियों पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या 195.39 जबकि वास्तविक संख्या 155.78 है। वहीं बिहार में अभी भी प्रति एक लाख की आबादी पर सिर्फ 100 पुलिसकर्मी हैं।
- एनसीआरबी 2020 के आँकड़ों के अनुसार अपराध दर के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है जबकि अपराधों के संदर्भ में ही इसे जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वाँ स्थान दिया गया है।
- गौरतलब है कि बिहार में आधुनिक युग में पुलिसिंग की शुरुआत वर्ष 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के लागू होने के साथ हुई थी
- स्वतंत्रता के बाद बिहार पुलिस ने 1952 में पुलिस कल्याण कोष, पुलिस अस्पताल और पुलिस सूचना कक्ष (पीआईआर) के निर्माण जैसी नवीन पुलिसिंग और कल्याणकारी प्रथाओं की शुरुआत के साथ एक समृद्ध परंपरा की विरासत सँभाली।
- 1958 में एक पुलिस आयोग की भी स्थापना की गई, जिसका कार्य पुलिस को लोगों के करीब लाना था।

नोट :